4 नवम्बर, 2009 को संसदीय सौध, नयी दिल्ली में "संसद और मीडिया" विषय पर आयोजित कार्यशाला में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री मो. हामिद अंसारी का उद्घाटन अभिभाषण

मीडिया सलाहकार समिति द्वारा "संसद और मीडिया" विषय पर आयोजित प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस सामयिक विषय पर चर्चा में भाग लेना एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रारम्भ में, मैं मीडिया सलाहकार समिति द्वारा डा. हरीश खरे और श्री विजय नायक की अध्यक्षता में पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख करना चाहूंगा। इसने राज्य सभा सचिवालय को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और प्रेस दीर्घा में मीडिया संगठनों के प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में पारदर्शी नीतियाँ बनाई हैं।

मैं इस अवसर पर मीडिया को, विशेषकर पिछले दो सत्रों के दौरान राज्य सभा की कार्यवाहियों को उत्कृष्ट ढंग से दर्शाने के लिए भी बधाई देता हूँ। यह कुछ संतोष की बात है कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों के द्वारा व्यापक रूप से सभा के विचार-विमर्श के कार्य पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो अल्पकालीन चर्चाओं तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में हुई बढ़ोत्तरी से स्पष्ट है, मीडिया के हमारे बन्धुगण इसके लिए बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

मित्रो**,**

पिछले कुछ वर्षों में मीडिया उद्योग में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुई है। हमने प्रचुर मात्रा में निवेश और मीडिया संगठनों का उद्भव देखा है। नयी प्रौद्योगिकी और उत्पाद जैसे आईपी टीवी, चल टीवी, तथा सामुदायिक रेडियो, नयी मीडिया शैली जैसे रियलिटी टीवी एवं विज्ञापनों के साथ उभरकर सामने आये हैं। समाचार मीडिया, मनोरंजन और दूरसंचार के

बीच पारस्परिक मेल हो जाने से लगता है कि पेशेवर पत्रकारिता, जनसम्पर्क, विज्ञापन तथा मनोरंजन के बीच अंतर तेजी से घट रहा है।

विकास का मूल्य सदैव ही चुकाना पड़ता है। हम मीडिया के तीव्र विकास के लिए चुकाए गए मूल्य का दो आयामों में आकलन कर सकते हैं।

सबसे पहले, मीडिया संगठनों के विकास के साथ-साथ उसी रफ्तार से मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किए जाने के समन्वित प्रयास के अभाव से लगता है कि गुणवत्ता में कमी आई है और मौजूदा मीडिया कर्मियों के लिए वर्तमान में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मीडिया समूह आन्तरिक मीडिया प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अभी तक के परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि मीडिया क्षेत्र के तीव्र विकास से यह तथ्य उजागर हुआ है कि मीडिया लोकतंत्र के स्तम्भों में से एकमात्र ऐसा स्तम्भ है जिसकी पहचान वाणिज्यिक और स्पष्टत: लाभ के लिए की जाती है। यद्यपि अपने पाठकों के प्रति मीडिया संगठनों का मुख्य व्यावसायिक कर्तव्य उन्हें समाचारों, दृष्टिकोणों और विचारों से अवगत रखना है, तथापि वाणिज्यिक तर्क से इन कंपनियों के शेयरधारकों के रूप में हितार्थियों का एक नया वर्ग सामने आता है।

इन गतिविधियों से ऐसे नए विचार सामने आए हैं जिनसे पेशेवर मीडिया निर्णयों के लिए मार्गदर्शन मिलता है। आज, पेशेवर पत्रकारों की मांगों का मीडिया कंपनियों के स्वामियों और हितार्थियों के हितों और उनके अन्योन्य-मीडिया हितों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया जाता है। इन परस्पर-विरोधी मांगों का पारस्परिक प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है और सार्वजनिक बहस का विषय है।

हाल ही में प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ ने कुछ राज्यों में हुए चुनावों के दौरान "पेड न्यूज" और "कवरेज पैकेज" के संबंध में किए गए व्यापक कदाचार का खुलासा किया है। भारतीय प्रेस परिषद् के, मीडिया के लिए, दिशा-निर्देशों में "सत्तासीन किसी पार्टी/सरकार की

उपलब्धियों के संबंध में सरकारी खर्चे पर कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं अथवा प्रकाशित नहीं करने" की बात कही गई है। इनमें यह भी कहा गया है कि "प्रेस किसी उम्मीदवार/पार्टी का प्रचार करने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन, वित्तीय अथवा अन्यथा, स्वीकार नहीं करेगी"। प्रेस परिषद् ने नोट किया है कि 'पेड न्यूज' प्रेस के कार्यकरण तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए भारतीय लोकतंत्र के लिए दोहरे खतरे का कारण बन सकती है। इसने लोगों के सूचना के अधिकार को संरक्षित करने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया है ताकि इससे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के चयन-स्तर का निर्णय करने में भ्रम उत्पन्न न हो।

देवियो और सज्जनो,

पत्रकारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिक आसानी से दिया जा सकता है तथा आज की कार्यशाला ऐसा ही एक प्रयास है। मुश्किल कार्य पत्रकारिता के व्यावसायिक एवं नैतिक आयाम को पुनर्जीवित करना है। इसका आरंभिक उपाय किसी मीडिया संगठन के संपादक की निर्णायक भूमिका को बहाल करना और समाचार सामग्री एवं कवरेज में सक्रियतावादी विपणन विभागों के हस्तक्षेप को निरुत्साहित करना है।

कार्यशाला में भाग ले रहे अधिकांश व्यक्ति संसद का कवरेज करते रहे हैं और मीडिया द्वारा संसदीय कवरेज के प्रकार्यात्मक मुद्दों से अवगत हैं। मुझे विश्वास है कि संसदीय विषयों और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में यह कार्यशाला आपके लिए सहायक होगी और आप पत्रकारिता संबंधी उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यशाला का उद्घाटन करता हूं और इसमें होने वाले विचार-विमर्श की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।